

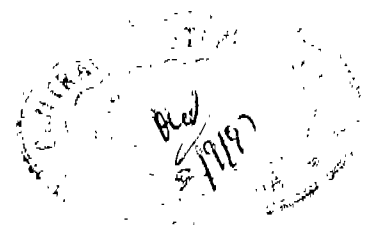


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 281]
No. 281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 1997/वैशाख 11, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 1997/VAISAKH 11, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1997

का० आ० 362 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) और नैशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) को, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 3-4-1997 की अधिसूचना सं० का० आ० 291 (अ) और 292 (अ) द्वारा विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जा चुका है, विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” गठित करती है। अधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जे० के० मेहरा से मिलकर बनेगा।

[फा० सं० 9/27/97-एन० ई०-1]

जी० के० पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 1997

S. O. 362 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Govt. hereby constitutes the “Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force (ATTF) and National Liberation Front of Tripura (NLFT) as unlawful associations declared as such by the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S. O. 291 (E) and 292 (E) dated 3-4-1997 respectively. The Tribunal shall consist of Mr. Justice J. K. Mehra Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 9/27/97-NE. I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

